वर्ष 23 | अंक 11 | सांचौर, रविवार 1 जून 2025 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25 | कुल पृष्ठ - 4

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

# मारवाड़ का मित्र

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

## त्राहिमाम एफआईजी

# फसली सहकारी ऋण वितरण प्रणाली का पोर्टल फिर बना किसानों के लिए व्यर्थ का झंझट

- एफआईजी पोर्टल की नाकामी मत्थे मढ़ने के लिए शीर्ष सहकारी बैंक के पास भारत सरकार का एक पोर्टल तैयार
- सहकारिता सचिवालय हेड इस एफआईजी पोर्टल संचालन की नाकामी के संबंध में एक शब्द सुनने को नहीं तैयार
- जिलों में बैंक प्रशासक यानि जिला कलक्टर पोर्टल सर्वर डाउन प्रकरण में निभा रहें धृतराष्ट्र की भूमिका

## एफआईजी की त्राहिमाम स्टोरी

प्रकाश वैष्णव
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर ।** राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त योजना के तहत 35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण देने का दावा बजट सत्र के दौरान विधानसभा में किया । लेकिन, इसका स्याह पहलू यह है कि आज मई-जून माह की भीषण गर्मी में सोसायटी के बाहर किसान ब्याज मुक्त योजना के लाभ लेने के लिए तरस रहें हैं । वजह सहकारिता विभाग का डींग मार एफआईजी पोर्टल नहीं चल रहा हैं । किसानों के यह हालात हैं कि उन्हें घंटो इंतजार करने के बाद भी फसली ऋण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ओर से फसली ऋण वितरण एवं वसूली कार्य के लिए लागू एफआईजी पोर्टल फिर सर्वर समस्या के फेर में अटक गया हैं, इस पोर्टल ने रबी सीजन की तरह फिर सोसायटी के आगे किसानों की भीड़ इकट्ठा कर दी हैं, यहां तक कि 45 डिग्री गर्मी वाले जिलों में भी किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए सोसायटी के आगे खड़े दिखाई दे रहें हैं । किसानों ने सरकार से इस पोर्टल प्रणाली को लेकर त्राहिमाम-त्राहिमाम की पुकार तक लगानी शुरू कर दी हैं । लेकिन पोर्टल की नाकामी का ढिंढोरा शीर्ष सहकारी बैंक ने पिछली बार की तरह इस बार भी केंद्र सरकार के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई पोर्टल) पर मढ़ दिया हैं । वर्तमान समय में खरीफ सीजन के दौरान सर्वर समस्या से जूझते इस पोर्टल ने फसली सहकारी ऋण वितरण प्रक्रिया को बदहाल अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया हैं ।

## सिर पीटने को मजबूर व्यवस्थापक

*राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना के तहत किसानों को जीरो फीसदी पर अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा हैं, किसानों को सोसायटी की ओर एफआईजी नामक पोर्टल से ऋण बांटा जाता हैं । वह पोर्टल हर बार की तरह इस बार भी सर्वर समस्या की फेर में अटक गया हैं, बताया जा रहा हैं कि इस पोर्टल को लागू करने के बाद से इसकी समीक्षा सहकारिता विभाग द्वारा एक बार भी नहीं की गई हैं, जिस सहकारिता से समृद्धि लाने के प्रयास केंद्र सरकार कर रही हैं, उस सहकारिता से किसान हतोत्साहित हो गए हैं, जिस एफआईजी पोर्टल को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अपनी उपलब्धि वाला पोर्टल बताकर बाहरी राज्यों के सहकारिता अधिकारियों के सामने डींग मारने का काम करता हैं, उसी पोर्टल को चलाने के लिए पैक्स व्यवस्थापकों को सोसायटी में सिर पीटने वाली स्थिती से गुजरना पड़ रहा हैं ।*

**सरकार की ओर से बढ़ाई तिथि के दौरान भी किसानों को ब्याज मुक्त योजना के नाम पर चुकाना पड़ रहा हैं मय ब्याज ऋण**

| प्रदेश में 7000 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत | पैक्स-लैंप्स से जुड़े हुए हैं 35 लाख से अधिक किसान सदस्य | ब्याज मुक्त योजना के तहत 1.50 लाख तक का ऋण कराया जाता मुहैया | सहकारिता मंत्री की विभाग के प्रति बेरुखी और गर्म मिजाज प्रमुख शासन सचिव सहकारिता की हठधर्मिता के चलते अधिकतर सहकारी समितियों में पैक्स कंप्यूटरीकरण की आड़ में प्रतिबंधित हैं ऋण प्रक्रिया |
|---|---|---|---|

## वर्ष 2019 का कारनामा

सहकारिता विभाग ने दुनिया से दो कदम आगे चलकर राजस्थान में किसानों को वर्ष 2019 में ही डिजिटलीकरण की ओट में छोड़ दिया था, जब आज भारत सरकार पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य कर रही हैं, तो राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में ही एफआईजी पोर्टल लागू करने का कारनामा कर दिया था, लेकिन किसान को आज भी फसली ऋण का लाभ लेने के लिए जूझना पड़ रहा हैं और ऋण वितरण के मामले में पैक्स और सीसीबी पहले भी आईसीयू में थे और एफआईजी पोर्टल बनने के बाद भी आईसीयू में ही नजर आ रहें है। भले ही सरकार ने किसानों पर 25 हजार करोड़ का सरकारी खजाना लुटाने के लंबे-चौड़े इश्तिहार दिए हो। लेकिन, हकीकत यह है कि सहकारिता विभाग का एफआईजी पोर्टल किसानों को लंबा भटकाने के बाद केवल नाममात्र की सौगात दे पाया हैं ।

## घंटो स्क्रीन हो जाती ब्लैंक

प्रदेश के कई जिलों से व्यवस्थापकों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, लैपटॉप एवं कंप्यूटर पर एफआईजी पोर्टल की स्क्रीन कई बार स्वत: ही ब्लैंक हो जाती हैं और किसी प्रकार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उन्होने बताया कि डीएमआर से लेकर किसानों की मनी तक विड्रॉल नहीं हो पाती हैं । एक किसान को मुश्किल से एक या दो घंटे इंतजार करने पर अगर किस्मत अच्छी हुई तो ऋण मिल जाता हैं, अगर नहीं हुई तो कंप्यूटर का प्रोसेस पुन: स्टार्ट करना पड़ता हैं और दुबारा स्टार्ट करने के बाद भी एफआईजी पोर्टल में किसी प्रकार की सहूलियत नहीं मिल पाती हैं । जबकि किसान ब्याज मुक्त योजना के भरोसे ही खरीफ फसल की बुवाई की उम्मीद में बैठा हैं ।

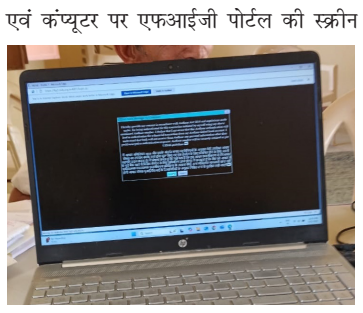

## एफआईजी के नाम पर नोटिस की धमकी

सहकारिता विभाग के शीर्ष सहकारी कार्यालय के हुक्मरानों द्वारा बाहरी राज्यों से आएं सहकारिता अधिकारियों को जिस एफआईजी पोर्टल को अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए संजोए रखा हैं, उस पोर्टल ने किसानों को समृद्धि के नाम पर भटकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हैं । गौरतलब है कि पिछले सीजन में भी एफआईजी पोर्टल की नाकामी की आवाज सहकारिता सचिवालय के हेड तक पहुंची, लेकिन अपने भारी रुतबे एवं गर्म मिजाज के लिए सहकारिता में मशहूर इस हेड ने आवाज उठाने वालों को ही नोटिस थमाने की धमकी दे डाली । जब सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव तक सहकारिता की जमीनी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं तो पैक्स के जरिए सहकार से समृद्धि कैसे आएगी ?

## सवाल अनेक जवाब सिर्फ एक....

*सहकारिता के इस पोर्टल को लेकर अधिकारियों का सिर्फ एक ही रटा-रटाया जवाब सुनने को मिलता हैं कि यह एफआईजी पोर्टल की नाकामी नहीं हैं, अरे ! भारत सरकार में आधार पोर्टल यूआईडीएआई का स्पोर्ट नही मिल रहा हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही हैं, हालांकि सहकारिता विभाग के इस पोर्टल की समस्या पिछले दो साल से एक ही जैसी हैं, जिसे दुरुस्त करने के बजाए सहकारिता विभाग के कार्यालय उलटे पोर्टल को और ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहें हैं । जिस पोर्टल से किसान के साथ सोसायटी एवं केंद्रीय सहकारी बैंक को वर्ष 2019 में जो कुछ उम्मीद जगी थी, वह आज के समय में डूब कर रह गई हैं, इसमें कुछ बदलाव की उम्मीद अब जिला स्तरीय सहकारी अधिकारियों से लेकर पैक्स कर्मियों को नहीं हैं ।*

## दत्ताणी और पोसीतरा सहकारी समिति के गठन प्रक्रिया संपन्न

**सिरोही ।** जिले में नवीन श्री सिध्धेश्वर बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. दत्ताणी के गठन प्रक्रिया ग्राम पंचायत दत्ताणी मुख्यालय पर संपन्न हुई, इस सोसायटी के गठन के लिए सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा 30 अप्रैल को स्वीकृति एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरोही द्वारा 6 मई को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं, जिसके क्रम में नवीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की कार्यवाही के साथ प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन ब्लॉक सहकारिता निरीक्षक शैलेन्द्रपालसिंह की मौजूदगी में संपन्न हुआ । जिसमें अध्यक्ष पद पर महिपालसिंह एवं उपाध्यक्ष पद पर पुनमसिंह, इसी तरह कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर आशीष, उम्मेदसिंह, गंगासिंह, थानाराम, सुरेंद्रसिंह, गणेशाराम, भंवरलाल, रजनादेवी, त्रिजादेवी, श्रवणकुमार को चुना गया हैं । इस दौरान कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक विक्रमसिंह, थानसिंह, डबानी सोसायटी अध्यक्ष सुल्तानसिंह, सेवानिवृत्त सीबीओ पुनमसिंह सोलंकी सहित अनेक किसान एवं ग्रामीण मौजूद रहें ।

## पोसीतरा सहकारी समिति का गठन

जिले में नवगठित पोसीतरा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की कार्यवाही के साथ प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यां का भी निर्वाचन ब्लॉक सहकारिता निरीक्षक शैलेन्द्रपालसिंह एवं सीसीबी अनादरा शाखा ऋण पर्यवेक्षक विक्रमसिंह मौजूदगी में संपन्न हुआ । जिसमें अध्यक्ष पद पर लक्ष्मणसिंह, उपाध्यक्ष पद पर सेरदान एवं कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर लादाराम, गणपतसिंह, आशाराम, रीटाकंवर, हीराराम, अमराराम, अमीयादेवी, मोतीराम, रुपाराम, धनाराम को चुना गया हैं

# बीमार पैक्सों के लिए नई नीति जल्द : शाह

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**नई दिल्ली।** केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि कोई भी पंजीकृत पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समितियां) बीमार न हों। पहले से परिसमापन (लिक्विडेशन) की स्थिति में पहुंच चुकी पैक्सों के त्वरित समाधान और उनके स्थान पर नई पैक्सों के गठन के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नई नीति लाने जा रही है। वह रविवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में अहमदाबाद में आयोजित सहकारी महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत पैक्सों की सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। साथ ही पूरी तरह बंद हो चुकी पैक्सों के स्थान पर नई पैक्स का पंजीकरण भी कराया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आगे भी पंजीकृत पैक्स वित्तीय रूप से बीमार नहीं होगी। शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को समृद्ध एवं विस्तार देने के लिए समूहों एवं संस्थाओं में जागरूकता, प्रशिक्षण एवं पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत सरकार ने इस वर्ष को सहकारिता वर्ष घोषित किया है। साथ ही सहकारिता में विज्ञान को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार का लक्ष्य 2029 तक देशभर में दो लाख नई पैक्स बनाने का है। पहले से बनी पैक्सों को बहुआयामी बनाया जा रहा है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। इसके लिए पैक्सों के साथ 22 अन्य व्यवसायों को जोड़ा गया है। गृह मंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में सर्कुलर इकोनामी को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारी स्वामित्व वाली कंपनी के जरिये आइसक्रीम, पनीर बनाने एवं दूध को ठंडा रखने की मशीनों और फैट मापन उपकरणों के निर्माण की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई पहल के तहत डेरी क्षेत्र में मृत पशुओं की खाल, हड्डियों एवं सींगों के उपयोग के लिए भी सहकारी समितियों का गठन करने का प्रयास किया जा रहा है। शाह ने कहा कहा कि सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार के स्तर पर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जरूरत है उन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचाने की। उन्होंने प्रत्येक जिले को सहकारिता आंदोलन से जोड़ने पर जोर दिया और कहा कि जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता के ढांचे को भी मजबूत करना होगा। केंद्र सरकार तीन-स्तरीय ढांचे की जगह एक चौथे स्तर का सहकारी ढांचा लागू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए समानुपातिक विकास का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें तीन मुख्य स्तंभ होंगे-सहकारिता को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना, तकनीक के जरिये पारदर्शिता लाने के साथ अधिक से अधिक नागरिकों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ने की तैयारी है।

## जालोर जिले में दो ग्राम पंचायत पर गठित नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति

**जालोर ।** जिले में दो नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार द्वारा की गई हैं, जिसमें सांचौर तहसील अंतर्गत पलादर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा, इसी प्रकार बागोड़ा तहसील की नवापुरा ध्वेचा ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा । इन समितियों का गठन होने से किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण, समय पर खाद-बीज एवं अन्य सहकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ मिलेगा । गौरतलब हैं कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सृजन एवं संचालन के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती हैं, जबकि नवीन गठन होने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति को राजस्व विभाग के अधिसूचना की अनुपालना में स्थानीय ग्राम पंचायत स्तर से गोदाम निर्माण के लिए 1500 वर्ग मीटर का नि:शुल्क भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम पांच वर्ष के लिए भवन भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

## डिफॉल्टर ऋणी कृषक 30 जून तक एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकेंगे

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जालोर।** राज्य के सहकारिता विभाग एवं शीर्ष सहकारी बैंक के निर्देशानुसार जिले की जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कृषि/अकृषि व्यक्तिगत अवधिपार एवं एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियाँ) में वर्गीकृत ऋणी सदस्यों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि/अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 लागू की गई है जिसकी प्रवर्तन अवधि बढ़ाकर 30 जून, 2025 तक की गई है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि/अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्रताधारक ऋणी कृषक सदस्य क्षेत्र की जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक की नजदीकी शाखा के शाखा प्रबंधक/क्षेत्रीय अधिकारी से सम्पर्क करें तथा कृषक सदस्य के विरूद्ध वसूली योग्य चुकता राशि जमा करवाकर कृषि/अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 में राहत राशि का लाभ प्राप्त करें। योजना की प्रवर्तन अवधि बढ़ाकर 30 जून, 2025 तक की गई है तथा शेष शर्तें यथावत रहेगी। इस तिथि तक डिफॉल्टर ऋणी किसानों द्वारा एक मुश्त समझौता योजनान्तर्गत लाभ नहीं लेने अथवा अपनी बकाया एनपीए/ओडी राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति में बैंक द्वारा उनके विरूद्ध अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

### योजना की प्रवर्तन अवधि बढ़ाकर 30 जून, 2025 तक की गई है तथा शेष शर्तें रहेगी यथावत

## हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री जेठाराम मेघवाल
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक
सिकवाड़ा जीएसएस

हमारे प्रिय जेठाराम मेघवाल व्यवस्थापक बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सिकवाड़ा के दी जालोर सैण्ट्रल को- ऑपरेटिव बैंक शाखा रामसीन में कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

**शुभेच्छु**

परमानंद पुरोहित - अध्यक्ष, मुपाराम रांगी - उपाध्यक्ष,
श्रीमती नेनुदेवी, जोराराम, श्रीमती कान कंवर, तुलसाराम, दुदाराम, जवेरसिंह, डायालाल, डूंगरसिंह, छगनलाल
एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण एवं किसान भाई, बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सिकवाड़ा तह. जसवंतपुरा, जिला-जालोर

**इस बार सहकारिता विभाग द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों पर विशेष फोकस**

# आठ सहकारिता सेवा अधिकारियों को मिला अतिरिक्त कार्यभार, अब बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर ।** प्रदेश में राजस्थान सहकारिता सेवा के आठ अधिकारियों को प्राथमिक भूमि विकास बैंक में सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार मिला हैं, हालांकि इनमें से चार पीएलडीबी में पदस्थ सचिव को आदेशों की प्रतिक्षा अवधि में रख दिया गया हैं । जबकि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सहकारिता विभाग में बड़ा फेरबदल होने की सुगबुगाहट जारी हैं, माना जा रहा हैं कि इस बार सहकारिता विभाग द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों पर विशेष फोकस किया जा रहा हैं और आरबीआई एवं नाबार्ड के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत प्रबंध निदेशक लगाने के साथ कई सालों से एक ही जगह जमे अधिकारियों का स्थानांतरण अन्यत्र होने जैसी कार्यवाही भी इस बार तबादलों में नजर आ सकती हैं । दूसरी ओर तबादलों की खबर बाहर निकलते ही स्थानीय नेताओं की अनुशंसा सहकारिता विभाग के सचिवालय तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं । अब देखना यह होगा कि क्या सहकारिता विभाग में इस बार केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक लगाने के लिए आरबीआई एवं नाबार्ड की ओर से जारी नियम की पालना हो पाती हैं या फिर स्थानीय नेताओं की अनुशंसा पिछली बार की तरह इस बार भी फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया नियमों पर पड़ेगी भारी ? हालांकि गुप्त सूत्रों के अनुसार विभाग में केंद्रीय सहकारी बैंकों में फेरबदल का सबसे बड़ा कारण राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना एवं केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना की क्रियान्विति में मंद गति से कार्य संपन्न होना बताया जा रहा हैं ।

**आरबीआई एवं नाबार्ड के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत प्रबंध निदेशक लगाने के साथ कई सालों से एक ही जगह जमे अधिकारियों का स्थानांतरण अन्यत्र होने जैसी कार्यवाही आ सकती हैं इस बार तबादलों में नजर**

## आठ अधिकारी को मिला अतिरिक्त कार्यभार

सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अजमेर पीएलडीबी में सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के महाप्रबंधक पवित्र पी. शिवदानी को दिया गया हैं, इसी प्रकार झुंझुनूं पीएलडीबी का अतिरिक्त कार्यभार विभा खेतान को एवं झालावाड़ पीएलडीबी का अतिरिक्त कार्यभार अवतारसिंह मीणा को, बांसवाड़ा पीएलडीबी का अतिरिक्त कार्यभार सुमन बैरवा को दिया गया हैं इनके अलावा डूंगरपुर पीएलडीबी का अतिरिक्त कार्यभार ओंकारमल बुनकर को, सवाईमाधोपुर पीएलडीबी का अतिरिक्त कार्यभार रोहित जैन को, चूरू पीएलडीबी का अतिरिक्त कार्यभार निशाकुमारी को तथा श्रीगंगानगर पीएलडीबी का अतिरिक्त कार्यभार सूर्यकांत को सौंपा गया हैं ।

## चार अधिकारी पदस्थापन आदेशों की प्रतिक्षा में

*सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी आदेशानुसार, राजस्थान सहकारिता सेवा की सहायक रजिस्ट्रार स्तर की अधिकारी आशा तंवर, संयुक्त रजिस्ट्रार के अधिकारी संजीव कुमार, उप रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी रामप्रदास मीना तथा सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी विष्णुप्रसाद मीणा को पदस्थापन आदेशों की प्रतिक्षा अवधि में कर दिया गया हैं ।*

## नामांकन में क्यों पिछड़ रहे सरकारी स्कूल

*सरकारी स्कूलों में हर सुविधा मुहैया कराने के बाद भी गिरता नामांकन चिंता का विषय है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में प्रवेश के प्रति बच्चों का मोहभंग होना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अमूमन हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे की सरकारी नौकरी लगे, लेकिन वह यह नहीं चाहते कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। यह सोचनीय प्रश्न है। हर साल जिला मुयालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का ढोल पीटा जाता है। शिक्षक से लेकर शिक्षा अधिकारियों को लक्ष्य दिया जाता है। इसके बावजूद नामांकन के दौड़ में हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। खासतौर से शहरी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के प्रति रुचि न के बराबर हो रही है। सरकार लगातार इन स्कूलों की संया बढ़ाने के साथ क्रमोन्नत करने पर जोर दे रही है। बड़ा सवाल यह है कि उस अनुपात में यहां विषय टीचर नहीं लगाए जाते। दूरस्थ इलाके में शिक्षक जाना पसंद नहीं करते। हालात यह है कि कहीं 10 नामांकन पर पांच शिक्षक लगे हैं तो सौ नामांकन पर महज दो टीचर हैं। यह बिगड़ता अनुपात शैक्षिक स्तर गिरा रहा। कोरोनाकाल के बाद से तो नामांकन लगातार गिरता जा रहा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकन का आंकड़ा छह साल में एक करोड़ से वापस 80 लाख पर आ गया है। शिक्षा विभाग, सरकार व अधिकारी यह समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर नामांकन में कमी क्यों आ रही। जबकि सरकार इस समय पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पोषाहार, प्राथमिक-उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को निशुल्क पुस्तकें, बालिकाओं को निशुल्क साइकिल, स्कॉलरशिप, टेबलेट, दूध समेत अन्य सामग्री की सुविधा निशुल्क दे रही है। अगले माह से नया शिक्षा सत्र 2025-26 शुरू होने वाला है। नामांकन बढ़ोतरी और ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूलों से जोड़ना शिक्षकों के लिए चुनौती होगा। इन चुनौतियों को सरकार को गंभीरता से लेना होगा। उन तमाम कारणों को टटोलना होगा, जिनसे बच्चे सरकारी स्कूल से दूर हो रहे हैं*

# फसल बीमा का कार्य पैक्स और सीएससी के माध्यम से करवाने के हों प्रयास : भूटानी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर।** राजस्थान में गोदाम निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में अन्न भण्डारण क्षमता बढ़ाने पर विशेष रूप से फोकस करते हुए नये गोदामों का निर्माण किया जाए। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करते हुए खरीद केंद्रों के निकट क्षेत्रों की बजाय अधिक उपभोग वाले क्षेत्रों में ज्यादा गोदाम निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाले व्यय में कमी आएगी। डॉ. भूटानी शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 एवं 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही पहलों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहकारिता से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे गोदामों के निर्माण की बजाय पैक्स को बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए तैयार किया जाए। फसल बीमा का कार्य पैक्स और कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से करवाये जाने के गंभीरता से प्रयास किए जाएं। साथ ही, राज्य की सहकारी समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर गठित की गई तीन नवीन सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन समितियों का सदस्य बनने से समितियों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। बैठक में राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संदीप वर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुबीर कुमार, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, उद्यानिकी आयुक्त श्री सुरेश कुमार ओला, राजफेड के प्रबंध निदेशक श्री मोहम्मद जुनैद एवं नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर डॉ. राजीव सिवाच सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

### मनरेगा के माध्यम से पैक्स द्वारा नर्सरी शुरू करने पर फोकस - राजपाल

श्रीमती राजपाल ने बताया कि राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदाम स्वीकृत किए गए हैं। नवनिर्मित अन्न भण्डारण गोदामों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर-कमलों से जून माह में करवाया जाना प्रस्तावित है। राज्य में पैक्स द्वारा अतिरिक्त कार्य शुरू किए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें उल्लेखनीय प्रगति है। साथ ही, सहकार में सहकारिता के अंतर्गत भी उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 प्रतिशत अनुदान पर कृषि एवं अकृषि ऋण की योजना को स्वयं सहायता समूहों के लिए विस्तारित किया जा रहा है। राजीविका के उत्पादों को कॉनफेड तथा जिला सहकारी भण्डारों के विक्रय केन्द्रों पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाया जाएगा तथा श्री अन्न आउटलेट खोले जाएंगे। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से पैक्स द्वारा नर्सरी शुरू करने पर फोकस किया जा रहा है। 'म्हारो खातो, म्हारो बैंक' अभियान के तहत डेयरी सोसायटियों के सहकारी बैंकों में खाते खोले जा रहे हैं।

### खाद का वितरण पैक्स के माध्यम से किया जाए - जैन

सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ जैन ने कहा कि माननीय केन्द्रीय सहकारिता मंत्री के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा खाद वितरण के लिए पैक्स को प्राथमिकता दी जाए तथा इफको एवं कृभको आदि संस्थाओं द्वारा भी इसके लिए पैक्स को ही आवंटन किया जाए। केन्द्र सरकार के स्तर से इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 25 से 30 प्रतिशत अधिक खाद का वितरण पैक्स के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। श्री जैन ने कहा कि खाद की पैक्स स्तर तक डिलीवरी की व्यवस्था की जाए तथा जिन पैक्स के पास फर्टिलाइजर लाइसेंस नहीं है, उन्हें दिलवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। श्री जैन ने कहा कि जन-धन केन्द्र लोगों की अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर खोले जाएं। जिन पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है, उन सभी में कॉमन सर्विस सेंटर बनाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन की समयबद्ध क्रियान्विति तथा दुग्ध उत्पादकों को अधिक रूपे कार्ड जारी करने के लिए नाबार्ड के स्तर से मॉनिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

### राज्य में 41 हजार से अधिक सहकारी समितियां

बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने प्रस्तुतीकरण देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत आयोजित की जा रही गतिविधियों एवं सहकार से समृद्धि कार्यक्रम की विभिन्न पहलों की प्रगति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि राज्य में 41 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनके एक करोड़ से अधिक सदस्य हैं। प्रदेश के लगभग 80 लाख कृषक सहकारिता से जुड़े हुए हैं। श्रीमती राजपाल ने बताया कि तक 4837 पैक्स को गो-लाइव किया जा चुका है और हम मई माह के अंत तक 5000 पैक्स गो-लाइव करने के लक्ष्य के बहुत निकट हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता के लिए राज्य की लगभग 2000 समितियों द्वारा आवेदन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की तीन नई सहकारी समितियों की नोडल एजेंसी के रूप में राजफेड को नामित किया गया है तथा उनके साथ एमओयू की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। साथ ही, नई एम-पैक्स एवं डेयरी सोसायटी के गठन की दिशा में भी राज्य में अच्छा कार्य हुआ है।

**नोट गिनने की मशीन तक पहुंचा बैंक**

# कर्जमाफी की राहत से खिले किसानों के चेहरे

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जालोर,** राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा घोषित मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 प्रदेशभर में किसानों को राहत पहुंचाने में सफल हो रही है। जालौर सहित जोधपुर संभाग के जिलों में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा है। पिछले कई वर्षों बाद जालौर सहकारी भूमि विकास बैंक में इन दिनों किसानों की भारी आवाजाही देखी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान सुबह से ही लाइन में लग रहे हैं। बैंक के कैश काउंटर पर इतनी व्यस्तता बढ़ गई है कि शीघ्र ही नोट गिनने की मशीन खरीदने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। 20 मई, 2025 तक 95 ऋणी किसानों ने मात्र 49 लाख रुपये की नकद राशि जमा कराकर योजना के तहत 1.10 करोड़ रुपये की राहत प्राप्त की है। जिले में 5800 से अधिक किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। राज्य सरकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए किसान बार-बार मुख्यमंत्री व सरकार का आभार जता रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 12 मार्च, 2025 को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य ऋणग्रस्त किसानों को राहत देकर उन्हें फिर से आर्थिक मुख्यधारा में जोड़ना है। इस उद्देश्य हेतु 200 करोड़ रुपये का बजट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु इसे पोर्टल आधारित प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। नियमित आधार पर राज्य, जिला और खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके, इसके लिए जानकारी अभियान भी चलाया जा रहा है। जोधपुर संभाग के सात जिलों में कार्यरत जिला सहकारी भूमि विकास बैंकों में लगभग 8200 ऋणी किसानों पर 170 करोड़ रुपये अवधिपार बकाया है। यदि ये किसान 62 करोड़ रुपये के मूलधन का भुगतान करते हैं, तो राज्य सरकार की ओर से 108 करोड़ रुपये की ब्याज राहत दी जाएगी। जालोर जिले में ऋणी कृषकों का 98.96 करोड़ का ऋण अवधिपार हो गया है। मुख्यमंत्री ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 योजना के तहत जिले में 67.27 करोड़ की ब्याज राहत जालोर के अवधिपार बकाया ऋणियों को देय होगी।

> "सभी पात्र किसानों से आग्रह है कि वे अपनी नजदीकी शाखा में जाकर योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। राज्य भूमि विकास बैंक के अधिकारी व बैंक सचिव भी समय-समय पर किसानों से सीधे संपर्क कर योजना की जानकारी दे रहे हैं।
>
> **- शुद्धोधन उज्ज्वल अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, खण्ड जोधपुर**

सफलता की कहानी....

# "सहकार से समृद्धि" के वाक्य को चरितार्थ करती उम्मेदाबाद ग्राम सेवा सहकारी समिति

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जालोर ।** ग्रेनाइट नगरी के रूप में देश भर में विख्यात जालोर के जनजीवन में जवाई नदी की भांति विशिष्ट गति है। इस गति को एक खास दिशा दी है, सहकारिता आंदोलन ने.....। समाज सुधार एवं गरीब कृषकों के उत्थान में सहकारिता की भूमिका को जालोरवासियों ने भली प्रकार समझा है। सहकारिता मंत्रालय की सहकार से समृद्धि पहल का जीवन्त रूप जालोर जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर स्थित उम्मेदाबाद ग्राम सेवा सहकारी समिति में दिखाई देता है।

सहकारिता आंदोलन सामाजिक सशक्तीकरण का अद्भुत हथियार है। इस सहकारिता के विचार की प्राथमिक प्रयोगशाला ग्राम सेवा सहकारी समिति है, जहां सहकारिता के चिन्तन का जमीन पर अंकुरण होता है। वर्ष 1961 में उम्मेदाबाद ग्राम सेवा सहकारी समिति नाममात्र सदस्यों एवं नाममात्र हिस्सा राशि से प्रारंभ हुई आज यह समिति संचालको के वित्तीय प्रबंधन एवं सदस्यों के समर्पण के परिणामस्वरूप वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। आज इस समिति में 1374 सदस्य एवं 5 करोड़ 74 लाख का सलाना टर्नऑवर हैं । इस समिति के 70 प्रतिशत सदस्य लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषक हैं, जिनके आर्थिक उन्नयन के साथ सामाजिक स्वावलम्बन पर भी समानान्तर ध्यान दिया जा रहा है। समिति के पास अपना मिनी सहकारी बैंक संचालित हैं, जिसने शीघ्र ही क्षेत्र की जनता का विश्वास जीत लिया बहुत तेजी से बैंक में खाताधारको की संख्या में वृद्धि हुई। मिनी बैंक के आकार का अनुमान इससे लगता है कि आज वर्ष 2023-24 में 3 करोड़ 51 लाख रूपये अमानते जमा हैं । जिस पर सलाना समिति को मुनाफा मिल रहा हैं, सिर्फ वर्ष 2023-24 में ही समिति को 5 लाख 25 हजार रुपए का लाभ मिला हैं । उम्मेदाबाद ग्राम सेवा सहकारी समिति आज इतनी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति में है कि अपने क्षेत्र के सदस्यों को उपभोक्ता ऋण एवं स्वयं सहायता समूहों को आवृत्ति एवं सावधि जमाओं के विरूद्ध ऋण उपलब्ध करा रही है। अपने खाताधारकों को यह समिति लॉकर सुविधा भी उपलब्ध कराती है, बड़ी संख्या में ग्राहक इस सुविधा का उपयोग कर रहे है। इतना ही नहीं, समिति के कॉमन सर्विस सेन्टर पर लाभान्वित होने वालों की संख्या स्वयं इसकी सफलता की कहानी बयान कर रही है। सीएससी पर बिजली के बिल, बीमा प्रीमियम की किश्त, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड बनवाना जैसी अनगिनत सेवायें जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। इन बहुआयामी कामों से समिति को अच्छा लाभ मिल रहा है।

जालोर जिले से 24 किलोमीटर दूर उम्मेदाबाद ग्राम सेवा सहकारी समिति का मुख्यालय

उम्मेदाबाद सहकारी समिति अंतर्गत संचालित भारतीय जन औषधि केन्द्र

**राज्य सरकार से अनुदानित कस्टम हायरिंग सेन्टर के जरिए किसानों को उपलब्ध कराए जा रहें सस्ती दरों पर कृषि यंत्र**

उम्मेदाबाद ग्राम सेवा सहकारी समिति का ड्रोन उद्यमी केंद्र

### किसानों को सस्ती दरों उपलब्ध कराए जा रहें कृषि यंत्र

प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप समिति में स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्र के माध्यम से खेती-किसानी के लिए रियायती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा हैं, समिति आर्थिक लाभ और सामाजिक सरोकार में सदैव संतुलन बनाकर चल रही है। इसी कड़ी में समिति की ओर से पीडीएस व्यवसाय का कार्य भी निष्पादित किया जा रहा हैं, जिससे समिति मुनाफा अर्जित कर रही हैं । साथ ही समिति की ओर से भारतीय जन औषधि केन्द्र की स्थापना कर ग्रामवासियों को बाजार मूल्य से बहुत कम दरो पर उच्चगुणवत्ता वाली दवाईयां भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

### सहकारिता की राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाओं से जुड़ी

*उम्मेदाबाद ग्राम सेवा सहकारी समिति आज देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको से जुड़ी हुई हैं, इफको की ओर से उम्मेदाबाद सहकारी समिति को ड्रोन उपलब्ध कराया हुआ हैं, जो स्थानीय किसानों के लिए खेती-किसानी में बहुत सहायक साबित हो रहा हैं, इस ड्रोन से किटनाशक एवं दवाईयों का छिड़काव किया जा रहा हैं । साथ ही इफको एवं कृभको के उत्पादों का विपणन भी समिति मुख्यालय पर किया जा रहा हैं । हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियां की सदस्यता भी समिति ने हासिल कर ली हैं, इतना ही नहीं भारतीय बीज सहकारी समिति की जालोर जिले में डिस्ट्रीब्युटरशीप भी समिति को मिली हैं ।*

### बचत के लिए आयोजित होते कैम्प

समिति मुख्यालय पर सरकार की अति महत्वाकांक्षी ब्याज मुक्त योजना के तहत अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरण एवं वसूली का कार्य शत-प्रतिशत पेपरलेस तौर पर किया जा रहा हैं । जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी समिति की ओर ग्रामीणों को दिया जा रहा हैं । इसके अलावा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले कृषि आदान-अनुदान के क्लेम भी किसानों को समिति स्तर से ही वितरित किए जाते हैं । साथ ही छोटी बचत की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए समिति द्वारा समय-समय पर कैम्पों का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में समिति के पास बचत खातों की 78 लाख रूपये एवं आवृत्ति खातों की 2 करोड़ 52 लाख रूपये की राशि जमा है।

**मधुसुदन शर्मा**
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक

*"उम्मेदाबाद ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक मधुसुदन शर्मा ने कहा कि समिति ने अपने आर्थिक संसाधनों के विकास के साथ सामाजिक सरोकारों पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित किया हैं । आने वाले समय में सहकार से समृद्धि के ध्येय वाक्य के तहत समिति कार्यक्षेत्र में सदस्यों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक सरोकार के नये प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे। साथ ही सहकारिता से छूटे हुए क्षेत्र में आर्थिक उन्नयन पर भी समानान्तर रुप से ध्यान दिया जा रहा हैं।"*

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/-☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details : Name: Marwad ka Mitra A/C No.: 11134027554 IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

# कृषक ऋण माफी पेटे बकाया 52 करोड़ का भुगतान और 6 साल से लंबित डीपीसी की मांग - आमेरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**सीकर ।** जिले की केंद्रीय सहकारी बैंक की आर्थिक स्थिती पर सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने चिंता जताई हैं, उन्होने राज्य सरकार की ओर से ऋण माफी के ब्याज पेटे बकाया 58 करोड़ की राशि को लेकर कहा हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बकाया 52 करोड़ का शत-प्रतिशत एनपीए प्रावधान करने से बैंक की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिससे बैंकिंग लाईसेंस के लिए निर्धारित 9 प्रतिशत सीआरएआर की पालना करने में भारी परेशानी बैंक के समक्ष आकर खड़ी हो गई हैं, उन्होने जिले के किसानों को समुचित फसली ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्तर बकाया 52 करोड़ रूपये का भुगतान सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक को करवाने की मांग उठाई है। दरअसल, ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सीकर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों व अधिकारियों की आम सभा होटल रघु पैलेस में नरेश कुमार माठ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, इनके साथ जयपुर से संगठन पदाधिकारी मनीष गंगावाल, राकेश कुमार गुर्जर, सर्वेश चौधरी, विनोद कुमार मीणा व दीपक सिंह जादौन भी अतिथि के रुप में शामिल रहें । इस दौरान सीकर जिले की विभिन्न शाखाओं व प्रधान कार्यालय से बड़ी संख्या में कर्मचारी व अधिकारियों उपस्थित रहें ।

## 17वें वेतन समझौते की कार्यवाही शुरू करने की मांग

सहकार नेता आमेरा ने आमसभा में बैंक कर्मियों को सम्बोधित करते हुए द्वि-पक्षीय लिखित संपन्न 16वें वेतन समझौते के तहत नियमानुसार देय बकाया यथा समर्पित, उपार्जित अवकाश का बढ़े हुए वेतनमान पर अंतर की राशि का भुगतान, बढ़े हुए वेतनमान पर मकान किराया भत्ते की राशि का भुगतान, JAIIB/CAIIB शैक्षणिक योग्यता पर 15वें वेतन समझौते के अनुसार देय वेतन वृद्धि का लाभ यथावत जारी करने, सेवा शर्तों को लेकर न्यायालय में लम्बित वाद के चलते रोके गये वेतन समझौता भुगतान का लाभ शीघ्र जारी करने, बैंकिंग सहायक वर्ग को अधिकारी पद पर कार्य एवजी नियमानुसार कार्यवाहक अधिकारी भत्ते का भुगतान जारी किया जाने की मांग उठाई हैं, साथ ही उन्होने जनवरी, 2024 से देय 17वें वेतन समझौते की कार्यवाही शुरू किये जाने की मांग की हैं ।

## 6 साल से डीपीसी लंबित

सहकार नेता आमेरा ने आमसभा को संबोधित करते हुए सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक में पिछले 6 साल से लम्बिल विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक कर कर्मचारियों एवं अधिकारियों को रिक्त पदों पर पदोन्नत करने की मांग उठाई, उन्होने कहा कि सरकार द्वारा सभी विभागों में वर्ष में दो बार डीपीसी कर पदोन्नति देने के आदेश एवं निर्णय के बावजूद बैंक प्रबन्धन द्वारा डीपीसी लम्बित रखे जाने से कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर भारी कुठाराघात हो रहा है। साथ ही, उन्होने सीकर बैंक में स्टाफ स्ट्रैन्थ की समीक्षा कर पदो में बढ़ोतरी करने, सीसीबी में पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने, राज्य में टू-टीयर सहकारी बैंकिंग व्यवस्था लागू करने तथा एक राज्य एक ग्रामीण बैंक की तर्ज पर एक राज्य एक सहकारी बैंक को लागू मांग दोहराई हैं ।

## पदाधिकारियों का निर्वाचन

आमसभा के दौरान पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया, जिसमें अध्यक्ष-मुकेश श्रीवास्तव, सचिव नरेश कुमार माठ, कोषाध्यक्ष-कुलदीप सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष सुशील जाखड़, महावीर सिंह राठौड़, महेश कुमार देवर, अमित सोनी, जयप्रकाश यादव, संगठन सचिव अंकित शर्मा, नेमीचंद बगाड़िया, श्रीमति ममता बिरानिया, सहायक सचिव-जयंत वशिष्ठ, कुमारी शैलेजा शर्मा, प्रदीप सिंह शेखावत, सहायक कोषाध्यक्ष-रवि प्रकाश मीणा निर्वाचित किये गये। कार्यकारिणी सदस्य व शाखा प्रतिनिधि-विजय कुमार मीणा, सोहन लाल, चंदेश माथुर, रामस्वरूप भूकर, धर्मेन्द्र मीणा, सुरेन्द्र वर्मा, देवेन्द्र सैनी, सुनील कुमार सरवा, हिमांशु सोनी, लखन मीणा, प्रतिज्ञा गुर्जर, ललित वर्मा, सोरभ चतुर्वेदी, रामसरण चौधरी, राजकुमार मीणा निर्वाचित किये गये हैं ।

## पीएफ पर मिलेगा 8.25 प्रतिशत ब्याज

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**नई दिल्ली,** केंद्र सरकार ने बीते वित्त ा वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज देने को अपनी अनुमति दे दी है। इसका लाभ निजी क्षेत्र के सात करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। इस अनुमति के साथ इन कर्मचारियों के भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) खाते में ब्याज की राशि जमा करने का रास्ता साफ हो गया है। इसी वर्ष फरवरी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त ा वर्ष 2024-25 के लिए जमा पर ब्याज दर को 8.25 प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया था। इस ब्याज दर को अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में भी पीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दिया गया था। एक श्रम मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने बीते वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को स्वीकृति दे दी है। श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में ईपीएफओ को भी जानकारी भेज दी गई है। अब इस स्वीकृत ब्याज दर के अनुसार, ईपीएफओ के सात करोड़ से अधिक सदस्यों के खातों में ब्याज की राशि जमा की जाएगी। ब्याज दर का निर्णय 28 फरवरी को ईपीएफओ के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की 237वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की थी।

## गेहूं खरीद ने तोड़ा चार साल का रिकार्ड

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**नई दिल्ली,** न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस बार गेहूं की खरीदारी ने पिछले चार वर्ष के रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया है। अभी तक 293 लाख टन से अधिक की खरीदारी हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा कि 312 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। खरीद की यह मात्रा वर्ष 2021-22 के बाद से सबसे अधिक है। चार वर्ष पहले 433 लाख टन खरीदारी हुई थी। खरीद की वर्तमान रफ्तार को देखते हुए सरकार का अनुमान है कि यह मात्रा 333 लाख टन तक पहुंच सकती है। सरकार इस वर्ष किसानों से 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदारी कर रही है। केंद्रीय पूल के लिए इस वर्ष 11 राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। गेहूं के बफर स्टाक को समृद्ध करने में सबसे ज्यादा पंजाब, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा का योगदान है। कुल खरीदारी का लगभग 70 प्रतिशत इन्हीं दोनों राज्यों से पूरा होता है। आश्चर्य है कि इस बार मध्य प्रदेश ने 77.70 लाख टन की खरीदारी कर हरियाणा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। राजस्थान में भी अभी तक 16.15 लाख टन की खरीदारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्य ने भी पहले के आंकड़े को पार कर लिया है। दोनों राज्य गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में शामिल हैं। फिर भी यहां ज्यादा खरीदारी नहीं हो पाती है। प्रत्येक वर्ष निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे रह जाता है।

## पैक्स व्यवस्थापकों के लिए सीएससी सेवाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**उदयपुर,** ''पैक्स-लैम्पस त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना की अंतिम कड़ी हैं'' जिसे सहकार से समृद्धि अभियान के तहत वित्तीय रुप से सक्षम बनाने के लिए सरकार एवं सहकारिता विभाग प्रतिबद्ध हैं, यह बात उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक अनिमेष पुरोहित ने कही । दरअसल उदयपुर जिले के प्रतापनगर स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय सभागार में सीसीबी के अधीन संचालित पैक्स-लैम्पस व्यवस्थापकों के लिए कॉमन सर्विस सेन्टर की विभिन्न सेवाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे संबोधित करते हुए प्रबंध निदेशक अनिमेष पुरोहित ने कहा कि सीएससी के माध्यम से सहकारी समितियां 300 से अधिक सेवाऐं प्रदान कर अपनी आय में बढोत्तरी कर सकती हैं। वही कार्यक्रम में अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खण्ड उदयपुर श्रीमती गुंजन चौबे ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पैक्स का दायरा बहुत बढ़ गया है। सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स-लेम्प्स को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरु की है, समिति व्यवस्थापको को उन सभी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए इसके अलावा क्षेत्रीय अंकक्षेक अधिकारी आशुतोष भट्ट, बैंक के कम्प्यूटर प्रोग्रामर हितेश पांचाल, उदयपुर जिले के सीएससी कोर्डिनेटर श्री हितेश पारीक एवं अधिशाषी अधिकारी डॉ मेहजबीन बानों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया । इस दौरान डॉ धर्मेश मोटवानी सहित उदयपुर, सलुम्बर, राजसमन्द तथा धरियावद क्षेत्र के 70 से अधिक पैक्स-लैम्पस व्यवस्थापक एवं बैंक कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहे ।

## इस वर्ष 2.5 लाख करोड़ का लाभांश दे सकता है आरबीआइ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**मुंबई,** अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि आरबीआइ द्वारा सरकार को दिया जाने वाला लाभांश इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहेगा। इसकी वजह यह है कि 2024-25 के दौरान रुपये में तेज गिरावट के कारण डालर की बिक्री के माध्यम से केंद्रीय बैंक की आय में उछाल आया है। यह लाभ 2025-26 में लाभांश के तौर पर सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। सरकार को दिया गया पिछला रिकार्ड लाभांश 2024-25 के दौरान 2.1 लाख करोड़ रुपये था, जिसने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने में मदद की थी। 2023-24 में सरकार को केंद्रीय बैंक ने 87,416 करोड़ रुपये रुपये का लाभांश चुकाया था। आरबीआइ की आय में सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाला ब्याज और नकदी की तंगी से जूझ रहे बैंकों को दिए गए फंड से होने वाली आय भी शामिल है। डीबीएस बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि इस साल लाभांश लगभग 2.5-2.7 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड उच्चस्तर पर पहुंच सकता है। आरबीआइ के बोर्ड ने गुरुवार को आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने के लिए बैठक की। इस बैठक में सरकार को दिए जाने वाले लाभांश की राशि तय की जाती है।

# डाटा गवर्नेंस सामने लाएगा खामियां, पंचायतों का होगा लक्षित विकास

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**नई दिल्ली,** पंचायतीराज मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडे स-2.0 के लिए किए अहम सुधार, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के राष्ट्रीय पोर्टलों का होगा आटोमैटिक एकीकरण सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण कर इन्हें नौ थीम में विभाजित करके पंचायतों के विकास का प्रयास चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाएं चल भी रही हैं, लेकिन विकास की गति सभी जगह समान नहीं है। यह भी चिंताजनक है कि सत्यापित आंकड़ों के आधार पर पंचायतों के विकास को परखने के लिए जब पंचायतीराज मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआइ) 1.0 जारी किया तो पाया कि देश की कोई पंचायत चऱ्ज श्रेणी में स्थान नहीं बना सकी। अब इंडेक्स के दूसरे चरण को कुछ सुधारों के साथ तैयार कराया जाना है। डाटा गवर्नेस को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के साथ संबंधित विभागों के राष्ट्रीय पोर्टलों के आटोमैटिक एकीकरण की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि खामियों को चिह्नित कर लक्षित विकास की रूपरेखा बनाई जा सके। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत एडंवासमेंट इंडेक्स तैयार करने की प्रक्रिया का शुभारंभ सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला से किया गया।

### 55 से बढ़कर 95 प्रतिशत पहुंची एसडीजी डाटा उपलब्धता

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में भारत के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की डाटा उपलब्धता 55 प्रतिशत से बढकर लगभग 95 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पीएआइ बेहतर मानकीकरण व सामंजस्य से समावेशी, परिणामोन्मुख शासन के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ा सकता है। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार राजीब कुमार सेन ने कहा कि पीएआइ-2.0 स्थानीय प्रयासों को राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिबद्धताओं से जो डने वाला एक शक्तिशाली सेतु है। पंचायतीराज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुशील कुमार लोहानी ने पीएआइ के उद्देश्य और प्रक्रिया को समझाया।

इसमें शामिल होने के लिए 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 250 से अधिक प्रतिभागी, संबंधित मंत्रालयों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं। पंचायतीराज मंत्रालय के इस कार्यक्रम में नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, ट्रांसफार्म रूरल इंडिया और पीरामल फाउंडेशन भी सहभागी हैं। कार्यशाला में प्रतिभागियों को बताया गया कि पंचायतों के विकास का सटीक विश्लेषण करने के लिए संकेतकों की संख्या पहले संस्करण में रहे 516 संकेतकों से घटाकर पीएआइ-2.0 में 147 में समायोजित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्रालयों के साथ विभागों के राष्ट्रीय पोर्टलों के आंकड़े आटोमैटिक एकीकृत होंगे और डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे। इसके आधार पर यह चिह्नित करना आसान होगा कि कौन-सी पंचायत सतत विकास लक्ष्यों की नौ थीमों (गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल-अनुकूल पंचायत, जल-पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत, सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला-अनुकूल पंचायत) में से किसमें आगे और किसमें पीछे है। उसे देखकर पंचायत विकास योजना तैयार की जा सकेगी। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए पंचायतीराज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि पीएआइ केवल डाटा संग्रह का माध्यम नहीं है, बल्कि पारदर्शी, जवाबदेह और प्रदर्शन-आधारित पंचायत स्तरीय शासन को संस्थागत बनाने का एक तंत्र है ।

## जेठाराम बने सीसीबी शाखा के कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जालोर ।** जिले की केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा रामसीन में जेठाराम मेघवाल को कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक बनाया गया हैं । उनकी अनुशंसा सीसीबी रामसीन शाखा प्रबंधक द्वारा की गई, जिसके क्रम में सीसीबी शाखा के ऋण वितरण, वसूली एवं अवधिपार ऋणों की वसूली को लेकर अग्रीम आदेशों तक सिकवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक जेठाराम मेघवाल को कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक का कार्यभार दिया गया हैं । इसके लिए सीसीबी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऋण पर्यवेक्षक को माहवार वेतन भत्ते समिति द्वारा एवं कार्यवाहक भत्ता बैंक द्वारा देय होगा । साथ ही, आदेश में चार्ज प्राप्त करने के उपरांत रामसीन शाखा अंतर्गत संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कार्य विधिवत रुप से संपादित करने के निर्देश दिए गए हैं । गौरतलब हैं कि जेठाराम वर्तमान में सिकवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति में मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक पद पर कार्यरत हैं, इनके व्यवस्थापक दायित्व निर्वहन के चलते आज सिकवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़े किसान सदस्यों को सहकारिता विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा हैं । वर्षो से सहकारी आंदोलन की सर्वश्रेष्ठ पहचान बनी सिकवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत कस्टम हायरिंग केंद्र के माध्यम से भी किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं जा रहें हैं ।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) रविवार, 1 जून 2025
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

सहकारिता विभाग | एक को डूबाने और दूसरे को उभारने की वर्षो से चली आ रही परिपाटी

# मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की क्रियान्वयन का खेमा अब सरपंचों तक पहुंचा....

## 2000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां असंतुलन की स्थिती मे रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति तो कभी सरकार की योजना पर प्रतिबंध जैसे आदेश

**प्रकाश वैष्णव**
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर ।** सहकारिता विभाग की एक को डूबाने और दूसरे को उभारने की वर्षो से चली आ रही परिपाटी आज भी जारी हैं, अर्थात् विभाग में भूमि विकास बैंकों को उभारने और केंद्रीय सहकारी बैकों और पैक्स को डूबाने का सिलसिला शुरू हुआ हैं । सहकारिता विभाग में प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की क्रियावन्यन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें इस योजना के क्रियावन्यन का खेमा गांव के सरपंचों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया, यानि सरपंचों को पात्र ऋणियों की सूची उपलब्ध करवाकर उनके माध्यम से पात्र व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने की बात सहकारिता प्रमुख शासन सचिव ने कही, उन्होने कहा कि योजना के पात्र व्यक्तियों को एकत्र कर सरपंच की उपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझाइस के माध्यम से भी ऋणी सदस्यों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वही इस योजना में प्रगति के क्रियावन्यन में ढिलाई बरतने पर चार सहकारिता सेवा अधिकारियों को पदस्थापन आदेशों की प्रतिक्षा अवधि में रखकर, आठ अधिकारियों को पीएलडीबी में सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया हैं । लेकिन आज गांवों में सहकारिता विभाग की योजनाओं में नियमों की बाध्यता के चलते आमजन दूसरी बैकों से नजदिकी बढ़ाने लगे हैं, हालांकि वर्तमान परिवेश में केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराईजेशन योजना की क्रियावन्यन में दिन-ब-दिन पिछड़ते प्रदेश के सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी पैक्स में रिक्त पदों संविदा कार्मिक नियुक्ति के आदेश तो कभी सरकार की ब्याज मुक्त योजना पर प्रतिबंध जैसे आदेश जारी कर योजना के क्रियावन्यन में हताशा एवं निराशा का प्रदर्शन किया जा रहा हैं । हालांकि प्रदेश में ब्याज मुक्त योजना को एफआईजी नामक पोर्टल ने इतना सर्वर प्रणाली में उलझाया योजना से जुड़े किसान व योजना को क्रियावन्यन करने वाली प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियां हायतौबा कर रही हैं तभी तो इस पोर्टल प्रणाली के लागू के पश्चात प्रदेश की 2000 से ज्यादा सहकारी समितियां असंतुलन की स्थिती में पहुंच गई हैं ।

**767 करोड़ रुपए माफी पेटे बकाया**

**राज्य सरकार की ओर से 767 करोड़ रुपए के मुकाबले सिर्फ 200 करोड़ रुपए की ही राशि मिल पाई**

### एफआईजी के बावजूद बढ़ रहा हैं ओवरड्यु

हाल ही में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ओर से प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैकों में अवधिपार ऋणों की वसूली को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 के मध्य खुले 427196 खातो में 28 अप्रैल 2025 तक ओवरड्यु की राशि 1622.31 करोड़ तक पहुंच गई हैं, इनमें बाड़मेर, भरतपुर, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, नागौर सीसीबी में ओवरड्यु 100 करोड़ से ज्यादा हैं, इसी तरह अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर सीसीबी में 50 करोड़ से अधिक तथा शेष सीसीबी में 50 करोड़ से कम ओवरड्यु बताया जा रहा हैं । इन ओवरड्यु की वसूली के लिए सहकारिता विभाग की ओर से किसी तरह के निर्देश जारी नहीं किए जा रहें हैं, क्योकि केंद्रीय सहकारी बैकों में ओवरड्यु की वसूली करने वाले अधिकारी यानि ऋण पर्यवेक्षकों के पद सालों से रिक्त पड़े है। कई सालों पहले ओवरड्यु के हालात के कारण ही भूमि विकास बैंकों की हालात पतली हो गई थी, इसी तरह आने वाले समय में सीसीबी में बढ़ते ओवरड्यु के चलते ऐसे हालात बनने की आंशका व्यक्त की जा रही हैं । फिर इसी तरह सरकार की एक को उभारने और दूसरे को डूबाने की नीति सालों बाद केंद्रीय सहकारी बैकों एवं पैक्स के लिए भी चल सकती हैं ।

### 764 करोड़ ऋण माफी पेटे बकाया

*राज्य सरकार की कर्ज माफी के विलंब भुगतान पर 8 प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा हुई, लेकिन छह साल के पश्चात भी सरकार उस राशि का भुगतान करना भूल गई हैं । इधर, आरबीआई ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ''राज्य सरकार से प्राप्य'' मद में दर्शाई राशि को फिजिकली प्राप्त नहीं होने पर बैंकों से शत-प्रतिशत प्रावधान करने का परिपत्र में स्पष्ट कहा हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से 767 करोड़ रुपए के मुकाबले सिर्फ 200 करोड़ रुपए की ही राशि मिल पाई, जिससे बाकि राशि का प्रावधान केंद्रीय सहकारी बैकों को एनपीए पेटे करना पड़ा । जिससे इनकी हालात पतली होकर रह गई हैं ।*

## सहकारी संस्थाओं की विभागीय ऑडिटर से ऑडिट कराने की बाध्यता वर्ष 2026-27 से होगी प्रभावी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर ।** प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स-लेम्पस), शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों के अतिरिक्त अन्य सहकारी सोसायटियों की सीए फर्म द्वारा लगातार 2 वर्ष की लेखापरीक्षा करने के उपरांत विभागीय ऑडिटर द्वारा लेखापरीक्षा सम्पादित करने की बाध्यता सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को एक परिपत्र जारी कर लागू की गई । हालांकि अब इस परिपत्र के संबंध में सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा आज स्पष्टीकरण जारी किया गया हैं, जिसके अनुसार ऑडिट योग्य सहकारी समितियों की संख्या के अनुपात में विभागीय निरीक्षकों की संख्या कम हैं, साथ ही पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना अंतर्गत Go-Live हो चुकी पैक्स की FIG पोर्टल पर ऑनसिस्टम ऑडिट शीघ्र पूर्ण करवाने और पैक्स के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सहकारी समितियों का वार्षिक वैधानिक अंकेक्षण भी निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाने की स्थिती को लेकर विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स-लेम्पस), शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों के अतिरिक्त अन्य सहकारी सोसायटियों की लेखापरीक्षा वर्ष 2026-27 तक सीए फर्म से करवाई जा सकती हैं । वही, विभागीय ऑडिटर द्वारा लेखापरीक्षा सम्पादित करने की बाध्यता वर्ष 2026-27 के पश्चात से प्रभावी होगी ।

## सहकारिता विभाग के 5 अधिकारियों का हुआ रिक्त पदों पर पदस्थापन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर ।** प्रदेश के सहकारिता विभाग में आदेशों की प्रतिक्षा अवधि में चल रहें पांच अधिकारियों का रिक्त पदों पर पदस्थापन किया गया हैं, इस संबंध में सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जगदीश कुमार सुथार को उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बाड़मेर एवं तब्बसुम कुरैशी को सहायक रजिस्ट्रार (लीव रिजर्व, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अजमेर तथा श्रीमती अल्का द्विवेदी को चुरू केंद्रीय सहकारी बैंक में अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी लगाया गया हैं, इसी प्रकार अशोक दीप पिंगोलिया को सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ कोटपूतली-बहरोड़, के अलावा सुरेन्द्र कुमार चौधरी को कॉनफैड जयपुर में प्रतिनियुक्ति सहायक रजिस्ट्रार लगाया गया हैं

सहकार से समृद्धि का वाक्य पैक्स के लिए बना दूर की कौड़ी | अलवर जिले में पैक्स के अस्तित्व को बचाने के लिए चुना कार्य बहिष्कार का रास्ता

# बदहाल स्थिती में पहुंची सहकारी आंदोलन की सबसे छोटी इकाई पैक्स, हताश कर्मी कार्य बहिष्कार की राह पर...

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**अलवर ।** अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र ने इस साल को सहकारिता वर्ष के रूप मानने की घोषणा की हैं, देश में पिछले चार साल से सहकार से समृद्धि का शोरगुल सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सुनाई दे रहा हैं तथा राज्य में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के कई दावें किए जा रहें हैं, लेकिन हकीकत इससे परे हैं, आज राजस्थान में सहकारी आंदोलन की धरोहर और सबसे अंतिम कड़ी के नाम से विख्यात पैक्स यानि प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी सोसायटी अपने वजूद को बचाने के लिए जुझ रही हैं, इसकी बदहाल स्थिती के लिए शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2019 में लागू ऋण वितरण पॉलिसी जिम्मेदार हैं, यह पॉलिसी आज राष्ट्रीय स्तरीय पैक्स कंप्यूटराइजेशन परियोजना के भी आड़े आ रही हैं । राजस्थान में सहकारी आंदोलन की अंतिम कड़ी पैक्स के पास केवल ब्याज मुक्त योजना में ऋण वितरण का ही मूल व्यवसाय हैं, इसमें भी कटौती के चलते घटते ब्याज मार्जिन से संस्थापन व्यय तक लाले इन दिनों पड़ने लगे हैं, जबकि पैक्स कंप्यूटराइजेशन में समितियों को गो-लाइव करने की सहकारिता विभाग की हेड को ऐसी ललक लगी हैं कि येन-केन पैक्स कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा हैं और इसके लिए मूल व्यवसाय को भी प्रतिबंधित करने से गांवों में पैक्स की रही सही साख भी टूट कर बिखरने लगी हैं । अब सवाल यह पैदा हो रहा हैं कि विभाग ने ऋण पर प्रतिबंध क्यों लगाया ? पैक्स कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तर पर व्यवस्थापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित क्यों नहीं हुए ? पैक्स व्यवस्थापकों से पैक्स कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के मामले में कम प्रगति के लिए चर्चा क्यों नहीं हुई ? क्या विभाग किसान और सहकारी समितियों के बीच बाड़ बनाने की कोशिश कर रहा हैं ? ऐसे बहुत सारे सवालों की झड़ी लगी हुई हैं और इसी कड़ी में प्रदेश के अलवर जिले की पैक्स का अस्तित्व बचाने के लिए हताश पैक्स कर्मियों ने दैनिक कार्य बहिष्कार की राह को चुना हैं ।

### अलवर के पैक्स कर्मी कार्य बहिष्कार की राह पर

इसी कड़ी में, फ़िलहाल प्रदेश के अलवर जिले में पैक्स कर्मियों द्वारा दैनिक कार्यो का बहिष्कार जारी हैं, इन कर्मियों की जिला स्तरीय मांगों पर भी सहमति नहीं बन पा रही हैं, आज सीसीबी प्रधान कार्यालय में व्यापक तौर पर चर्चा के बावजूद भी विभाग के अधिकारी कान में जूं तक रेंगाने को तैयार नहीं हैं । दरअसल, अलवर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों द्वारा चार दिन पहले बैंक प्रशासक एवं जिला कलेक्टर अलवर को ज्ञापन सौंपकर दैनिक कार्य बहिष्कार शुरू करने के पश्चात आज सीसीबी प्रधान कार्यालय में यूनियन जिला अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार सैदावत, संघर्ष समिति संयोजक ओमप्रकाश शर्मा सहित 21 सदस्यों के शिष्ट मंडल की प्रबंध निदेशक देवदास बैरवा के साथ बैंक प्रबंधन की मौजूदगी में वार्ता हुई, लेकिन एक भी मांग पर सहमति नहीं बनी और जिले में पैक्स के दैनिक कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय पुन: राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन जिला यूनिट अलवर द्वारा लिया गया ।

## सहकारी बैंकों में प्लेसमेंट एजेंसी से कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करें सरकार-आमेरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर ।** प्रदेश के राज्य सहकारी बैंक, 29 केंद्रीय सहकारी बैंक एवं एसएलडीबी, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों में पिछले कई सालों से प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर बैंकिग कार्य कर रहें समस्त कार्मिकों को नियमित करने की मांग सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव एवं पंजीयक को पत्र लिखकर उठाई हैं । उन्होने बताया कि राज्य सरकार ने प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिको को नियमित करने के के लिए कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन करने की बजट घोषणा की हैं । जिसकी पालना में समस्त विभागों की ओर से प्लेसमेंट एजेंसी व संविदा कर्मियों की सूचना मांगी गई है । लेकिन सहकारिता विभाग द्वारा अपेक्स बैंक, सीसीबी, पीएलडीबी से इन संविदा कर्मियों की किसी प्रकार की सूचना नहीं मांगी गई हैं । उन्होने सहकारी बैंकों में संविदा पर कार्यरत लगभग 1000 कर्मियों की सूचना लेने के पश्चात कार्मिक विभाग की प्रक्रिया से जोड़ने की मांग उठाई हैं । सहकार नेता आमेरा ने बताया कि राज्य के सभी सहकारी बैंकों में पिछले 35 वर्षों से सहायक कर्मी (चपरासी) एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई भर्ती नहीं हुई है । इन बैंकों में नियमित कार्य प्रकृति के इन रिक्त पदों पर प्लेसमेंट एजेंसी से संविदा पर सहायक कर्मी, चपरासी, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में योग्य, शिक्षित व लंबे बैंक कार्यानुभव से दक्ष कार्मिक नियोजित है । वही बैंकों में रिक्त पद की स्थिती को लेकर आमेरा ने सुझाव दिया कि इन बैंकों में आज भी पद रिक्त है, जिन पर कार्मिक की ज़रूरत है तो इन अनुभवी, जांचे परखे कार्मिक से बेहतर विकल्प हो नहीं सकता, उनके अनुसार, इन कामिकों को नियमित किया जाना समाजिकता, मानवता, न्यायोचित व क़ानूनी रूप से भी व्यावहारिक होगा ।

## सहकारी समितियों में नियमानुसार चार्ज नहीं लेने पर व्यवस्थापक होंगे जिम्मेदार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**हनुमानगढ़,** ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों द्वारा नियमानुसार चार्ज नहीं लिया जा रहा। ऐसे में समिति में घोटाला या अन्य तरह का मामला उजागर होने पर मौजूदा व्यवस्थापक जिम्मेदार होंगे। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अमीलाल सहारण ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों द्वारा चार्ज का लेन-देन सही तरीके से नहीं लेकर नए सिरे से ही प्रारंभ कर दिया जाता है जो गलत है। यानी किसी समिति में जिस दिन व्यवस्थापक चार्ज लेता है वो उसी दिन से आगे का लेन-देन नोट करता है, जबकि पूर्व में नियुक्त व्यवस्थापक से नियमानुसार चार्ज लेकर स्टॉक सहित अन्य सामान का लिखित में लेन-देन होना चाहिए। इसकी सूचना बैंक शाखा एवं अधिशाषी अधिकारी को भी देनी चाहिए। कोई व्यवस्थापक चार्ज नहीं देता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 109 में वाद दायर कर चार्ज लिया जाता है।

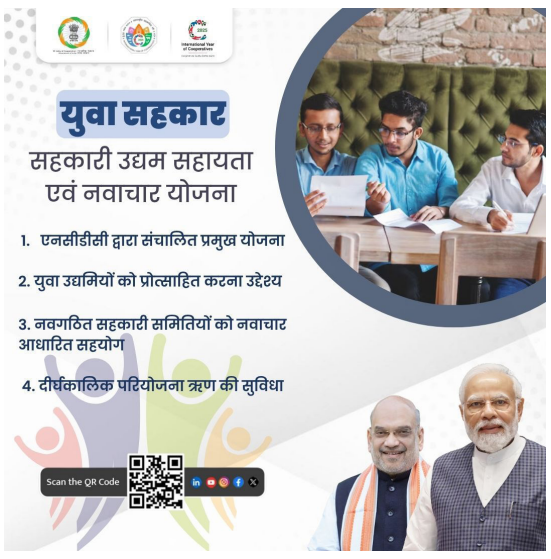


जल
ही जीवन है...

सदैव उत्तरोत्तर प्रगति की राह पर ग्राम सेवा सहकारी समिति
उम्मेदाबाद बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड उम्मेदाबाद
पंचायत समिति - जालोर, जिला - जालोर

मधुसूदन शर्मा
व्यवस्थापक

नगेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
2025
International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

छतराराम मेघवाल
सहायक व्यवस्थापक

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

■ आर.डी, एफ.डी एवं बचत खाते आकर्षक ब्याज दर पर, ■ ग्राम सेवा सहकारी समिति में लॉकर सुविधा उपलब्ध, ■ उपभोक्ता ऋण एवं स्वयं सहायता समूहों को आर.डी, एफ.डी जमाओं के विरूद्ध ऋण, कस्टम हायरिंग केंद्र के माध्यम से खेती-किसानी के लिए रियायती दरों पर कृषि यंत्र, ■ ड्रोन के माध्यम से उर्वरक का फसलों पर स्प्रे, ■ सीएससी पर बिजली के बिल, बीमा प्रीमियम की किश्त, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड बनवाने जैसी अनगिनत सेवायें

स्मार्ट खेती, ड्रोन और डेटा संचालित निर्णय-प्रक्रियाएं भारत के कृषि क्षेत्र को नई दिशा दे रही हैं।

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री जेठाराम मेघवाल
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक
सिकवाड़ा जीएसएस

हमारे प्रिय जेठाराम मेघवाल व्यवस्थापक बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सिकवाड़ा के दी जालोर सैण्ट्रल को- ऑपरेटिव बैंक शाखा रामसीन में कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

शुभेच्छु
नीतीराजसिंह भाटी व्यवस्थापक सावित्र जीएसएस, हकाराम व्यवस्थापक धानसा जीएसएस, अमराराम व्यवस्थापक मोदरा जीएसएस, पीराराम व्यवस्थापक वासड़ा धनजी जीएसएस, चीनाराम व्यवस्थापक सोमता जीएसएस

## सहकारी समितियों के लिए परिवहन और खरीद प्रक्रिया के पुराने आदेश रद्द

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर।** राज्य की कय विक्रय सहकारी समितियों और सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों के लिए परिवहन और खरीद प्रक्रिया को लेकर 11 सितंबर 2013 को जारी आदेश को सहकारिता विभाग ने निरस्त कर दिया है। इससे पहले जारी आदेश राज्य सरकार के पारदर्शिता अधिनियम (आरटीपीपी) 2012 और नियम 2013 से मेल नहीं खाता था। नए आदेश के अनुसार, सभी सहकारी समितियों को अब अपने परिवहन और खरीद संबंधी कार्यों में पारदर्शिता अधिनियम और नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने स्पष्ट किया कि पुराना आदेश अब अप्रासंगिक हो चुका है और इसे आधिकारिक रूप से प्रत्याहारित किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी सहकारी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे खरीद और परिवहन प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। यह कदम सहकारी समितियों के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

### सभी सहकारी समितियों को अब अपने परिवहन और खरीद संबंधी कार्यों में पारदर्शिता अधिनियम और नियमों का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म पसावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।